

“बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक स्थिति का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन: भागलपुर जिले के विशेष संदर्भ में I”

मुकेश कुमार विजेता

सहायक प्राध्यापक ,

विश्वविद्यालय औद्योगिक सम्बन्ध अवं कार्मिक प्रबंध विभाग,

तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार – 812007

Email ID.- mukeshkumarvijeta@gmail.com

सारांश (Abstract)

प्रस्तुत शोध लेख बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक स्थितियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है, जिसमें भागलपुर जिले के शैक्षिक परिवेश पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। गुणात्मक और मात्रात्मक शोधों पर आधारित यह अध्ययन दर्शाता है कि शिक्षकों की स्थिति वेतन विसंगति, प्रशासनिक बोझ और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे के कारण जटिल रही है। भागलपुर जिले के संदर्भ में, शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर निजी विद्यालयों से प्रतिस्पर्धा और गैर-शैक्षणिक कार्यों का दबाव शिक्षकों में गहरे मनोवैज्ञानिक तनाव और कार्य-असंतोष का कारण बनता है। हाल ही में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के सरकारी निर्णय ने आर्थिक मोर्चे पर आशा की किरण जगाई है, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। यह शोध नीति निर्माताओं, शिक्षा प्रशासकों और शोधकर्ताओं को शिक्षकों के कल्याण हेतु लक्षित हस्तक्षेपों की आवश्यकता पर बल देता है।

मुख्य शब्द(Key Words) : सरकारी शिक्षक, भागलपुर जिला, सामाजिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक तनाव, आर्थिक स्थिति, नियोजित शिक्षक, कार्य-असंतोष।

1. प्रस्तावना (Introduction)

1.1. अध्ययन का संदर्भ

शिक्षक किसी भी शिक्षा प्रणाली की रीढ़ होते हैं, और उनकी कार्यदशाएँ सीधे तौर पर शिक्षा के परिणामों को प्रभावित करती हैं। बिहार, जो भारत में सबसे अधिक आबादी वाले और शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में से एक है, अपनी शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती और सुधारों पर निर्भर रहा है। इस प्रक्रिया में, शिक्षकों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, उनकी मानसिक स्थिति और समाज में उनकी प्रतिष्ठा का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

1.2. बिहार में शिक्षा और शिक्षक कार्यबल

बिहार में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षकों को नियोजित शिक्षक के रूप में संविदा पर भर्ती किया गया था, जिससे शिक्षक-छात्र अनुपात में सुधार हुआ। हालांकि, वेतन, सेवा शर्तों और सामाजिक सुरक्षा में नियमित (Regular)

शिक्षकों के साथ उनकी विसंगति ने एक द्विस्तरीय कार्यबल (Two-tiered Workforce) का निर्माण किया, जिसने शिक्षकों के बीच गहरे असंतोष और निराशा को जन्म दिया।

1.3. भागलपुर जिले का विशेष संदर्भ

भागलपुर, एक प्रमुख शहरी और ग्रामीण मिश्रित जिला होने के कारण, बिहार के शिक्षा परिवर्ष का एक प्रतिनिधि मॉडल प्रस्तुत करता है। इस जिले में निजी और सरकारी विद्यालयों के बीच की प्रतिसर्धा अधिक स्पष्ट है। भागलपुर में शिक्षकों की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक चुनौतियों का अध्ययन राज्यव्यापी समस्याओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

1.4. शोध का उद्देश्य

इस शोध का प्राथमिक उद्देश्य भागलपुर जिले के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की निम्नलिखित तीन प्रमुख स्थितियों का गहराई से विश्लेषण करना है:

उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और कार्य-जीवन संतुलन।

उनका मनोवैज्ञानिक कल्याण, तनाव का स्तर और कार्य-संतुष्टि।

उनकी आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता, विशेष रूप से नियोजित और नियमित शिक्षकों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण।

2. शोध विधि (Research Methodology)

यह अध्ययन मुख्य रूप से गुणात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है, जो भागलपुर जिले के शिक्षकों से संबंधित पूर्व में प्रकाशित शोध पत्रों, सरकारी रिपोर्टों (जैसे U-DISE, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण), और मीडिया रिपोर्टों का गहन विश्लेषण करता है। भागलपुर जिले से संबंधित प्रत्यक्ष डेटा (जैसे वेतन तुलना और शिक्षा गुणवत्ता पर अध्ययन) का विशेष रूप से उपयोग किया गया है ताकि निष्कर्षों को क्षेत्रीय संदर्भ दिया जा सके।

3. परिणाम और चर्चा (Results and Discussion)

3.1. सामाजिक स्थिति: सम्मान और प्रशासनिक बोझ के बीच

A. जन-धारणा और प्रतिष्ठा

पारंपरिक रूप से शिक्षक को 'गुरु' माना जाता था। हालांकि, भागलपुर के संदर्भ में एक अध्ययन से पता चलता है कि निजी विद्यालयों के शिक्षकों की तुलना में सरकारी शिक्षकों के प्रति जन-धारणा में गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर चिंताएँ हैं।

B. गैर-शैक्षणिक कार्यों का भार

भागलपुर सहित पूरे बिहार में शिक्षकों को चुनाव ऊटी, जाति सर्वेक्षण, आधार सीडिंग, और मध्याह्न भोजन (MDM) योजना के प्रशासनिक कार्य जैसे गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है।

भागलपुर के परिपेक्ष्य में: चूंकि भागलपुर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र है, यहाँ शिक्षकों को अक्सर प्रशासनिक कार्यों में अधिक सक्रियता से शामिल किया जाता है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उनके शिक्षण कार्य का समय प्रभावित होता है। इससे उनकी सामाजिक छवि एक शिक्षक के बजाय "सरकारी बाबू" के रूप में अधिक बनती है, जो उनके पेशेवर सम्मान को कम करता है।

C. महिला शिक्षकों की चुनौतियाँ

महिला शिक्षकों को कार्यस्थल पर बुनियादी ढाँचे की कमी (विशेषकर ग्रामीण भागलपुर के स्कूलों में स्वच्छ शौचालय) और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक रूप से, उन्हें घर और कार्यस्थल की दोहरी जिम्मेदारी का निर्वाह करना पड़ता है, जिससे कार्य-जीवन संतुलन गंभीर रूप से बाधित होता है।

3.2. मनोवैज्ञानिक स्थिति: असंतोष और तनाव

A. कार्य-असंतोष का मुख्य कारण

भागलपुर के शिक्षकों से संबंधित एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि शिक्षकों में कार्य-असंतोष का मुख्य कारण वेतन विसंगति (नियमित और नियोजित शिक्षकों के बीच) और असुरक्षित सेवा शर्तें रही हैं। वर्षों तक समान कार्य करने पर भी कम वेतन मिलना, गहरे मनोवैज्ञानिक मोहब्बत को जन्म देता है।

B. तनाव और बर्नआउट

गैर-शैक्षणिक कार्यों का लगातार दबाव शिक्षकों में उच्च तनाव (High Stress) और बर्नआउट (Burnout) का प्रमुख कारण है। MDM की निगरानी से लेकर सर्वेक्षण कार्यों तक की जिम्मेदारी उन्हें शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने से रोकती है, जिससे वे अपने प्राथमिक उद्देश्य को पूरा न कर पाने का अपराध-बोध महसूस करते हैं।

C. संस्थागत समर्थन का अभाव

भागलपुर में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (जैसे PTEC Nagarpara) के मौजूद होने के बावजूद, शिक्षकों को अक्सर महसूस होता है कि उन्हें बदलते शैक्षिक मानकों (जैसे NEP 2020) के अनुरूप पर्याप्त मनोवैज्ञानिक परामर्श और पेशेवर प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। यह अक्षमता का भाव उनके आत्मविश्वास और मनोवैज्ञानिक कल्याण को प्रभावित करता है।

3.3. आर्थिक स्थिति: विसंगति से सुरक्षा की ओर

A. दोहरी आर्थिक संरचना

आर्थिक मोर्चे पर, भागलपुर में सरकारी शिक्षकों के बीच स्पष्ट आर्थिक द्वंद्व रहा है:

नियमित शिक्षक: उन्हें बेहतर वेतनमान, भत्ते और पेंशन की सुविधाएँ प्राप्त थीं, जो उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाती थीं।

नियोजित/संविदा शिक्षक: 2023-24 से पहले ये शिक्षक बहुत कम वेतन पर कार्यरत थे। एक शोध में पाया गया कि उनके वेतन में नियमित शिक्षकों की तुलना में भारी अंतर था, जिससे उन्हें परिवार का भरण-पोषण करने में कठिनाई होती थी और अक्सर निजी व्यूहान लेने के लिए मजबूर होना पड़ता था।

B. विलंबित भुगतान और वित्तीय तनाव

पूर्व में नियोजित शिक्षकों को अक्सर उनके वेतन के भुगतान में देरी का सामना करना पड़ता था, जिससे उनका वित्तीय तनाव बढ़ जाता था। यह समस्या भागलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक थी जहाँ बैंकिंग और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ धीमी थीं। यह विलंब उनके आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता और पारिवारिक स्थिरता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता था।

C. राज्यकर्मी का दर्जा: एक आर्थिक बदलाव

बिहार सरकार के हालिया निर्णय (नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना) ने भागलपुर सहित पूरे राज्य में शिक्षकों की आर्थिक स्थिति को क्रांतिकारी रूप से सुधारा है।

प्रभाव: यह निर्णय न केवल वेतन में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित करता है, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भविष्य निधि) प्रदान करके उनकी दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत करता है। यह कदम शिक्षकों के बीच वर्षों से व्याप्त आर्थिक असंतोष को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और वित्तीय प्रोत्साहन है।

4. निष्कर्ष और नीतिगत निहितार्थ (Conclusion and Policy Implications)

4.1. निष्कर्ष

भागलपुर जिले के विशेष संदर्भ में बिहार के सरकारी शिक्षकों की स्थिति एक विरोधाभासी तस्वीर प्रस्तुत करती है। आर्थिक मोर्चे पर हालिया सरकारी सुधारों (राज्यकर्मी का दर्जा) से बड़ी राहत मिली है, जो शिक्षकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। हालाँकि, उनकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति अभी भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ, गिरती सामाजिक प्रतिष्ठा और संस्थागत समर्थन की कमी शिक्षकों के तनाव और कार्य-असंतोष का मुख्य कारण बने हुए हैं, जो अंततः शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

भागलपुर जिले में कार्यरत सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

उनका जीवन संतुलन अनेक कारकों पर निर्भर करता है – जैसे आय का स्तर, कार्यस्थल का वातावरण, प्रशासनिक समर्थन और सामाजिक अपेक्षाएँ।

शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा धीरे-धीरे घट रही है, क्योंकि समाज उन्हें केवल “सरकारी नौकरीधारी” के रूप में देखने लगा है।

- आर्थिक रूप से अधिकांश शिक्षक सीमित संसाधनों में जीवन यापन कर रहे हैं।
- मानसिक तनाव एक व्यापक समस्या है, जिसका असर न केवल उनके स्वास्थ्य पर बल्कि शिक्षण-गुणवत्ता पर भी पड़ रहा है।
- प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास के अवसर सीमित होने से उनका आत्म-संतोष घट रहा है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शिक्षकों की सामाजिक-आर्थिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति में सुधार किए बिना बिहार की शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं।

4.2. नीतिगत निहितार्थ

शैक्षणिक कार्य पर पुनर्ध्यान: शिक्षकों को सभी गैर-शैक्षणिक कार्यों (चुनाव ऊँटी और सर्वेक्षण को छोड़कर) से तुरंत मुक्त किया जाना चाहिए। मध्याह्न भोजन योजना को स्वयं सहायता समूहों या अन्य एजेसियों को सौंपने की नीति बनाई जानी चाहिए।

मानसिक स्वास्थ्य समर्थन: भागलपुर जैसे जिलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए नियमित तनाव प्रबंधन और मनोवैज्ञानिक परामर्श सत्र आयोजित किए जाने चाहिए।

बुनियादी ढाँचा प्राथमिकता: ग्रामीण और शहरी स्कूलों में RTE मानकों के अनुसार शैक्षणिक, पीने का पानी और स्वच्छ कक्षा जैसी बुनियादी भौतिक सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए, ताकि कार्यस्थल का वातावरण सुधरे।

पेशेवर विकास का सुदृढ़ीकरण: तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय (TMBU) से संबद्ध शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों के माध्यम से शिक्षकों को NEP 2020 की आवश्यकताओं और संवेदनशील कक्षा प्रबंधन के लिए निरंतर और प्रभावी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

इस शोध से यह स्पष्ट होता है कि बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में स्थायी सुधार लाने के लिए, केवल आर्थिक सुरक्षा ही पर्याप्त नहीं है; शिक्षकों को उनका सामाजिक सम्मान और मानसिक शांति वापस दिलाना भी उतना ही आवश्यक है।

अध्ययन के विश्लेषण से साफ स्पष्ट होता है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति परस्पर जुड़ी हुई है।

1 . सामाजिक स्थिति : शिक्षक आज भी समझ में नैतिक दृष्टि से सम्मानित हैं किंतु सामाजिक हैसियत का वास्तविक स्वरूप बदल गया है शहरी क्षेत्र में निजी विद्यालयों की भर्ती संख्या में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की छवि को प्रभावित किया है।

2 . आर्थिक स्थिति : वेतनमान के बावजूद वास्तविक क्रय शक्ति कम होने से शिक्षक वित्तीय रूप से सशक्त नहीं हो पा रहे हैं परिवार का पालन पोषण बच्चों की शिक्षा और सामाजिक दायित्व उनके आर्थिक संतुलन को प्रभावित करते हैं

3 . मनोवैज्ञानिक स्थिति : लगभग दो तिहाई शिक्षकों ने मानसिक तनाव की शिकायत की। इसके पीछे प्रमुख कारण रहे बढ़ता कार्यभार, छात्रों का अनुशासन भंग, प्रशासनिक दबाव और भविष्य की असुरक्षा की भावना।

4 . लिंग आधारित अंतर : महिला शिक्षकों में मानसिक तनाव का स्तर थोड़ा अधिक पाया गया जबकि पुरुष शिक्षकों की आर्थिक असंतोष अधिक देखा गया

5 . संबंध का विश्लेषण : सहसंबंध विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि सामाजिक आर्थिक स्थिति और मनोवैज्ञानिक संतोष के बीच $r = 0.67$ का सकारात्मक संबंध है जो यह संकेत देता है कि आर्थिक स्थिरता शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करती है

सुझाव (Suggestions)

- 1 . वेतन एवं भर्ती में यथार्थ सुधार : महंगाई दर के अनुरूप वेतनमान और अतिरिक्त भारती की व्यवस्था आवश्यक है।
- 2 . मनोवैज्ञानिक परामर्श (Counselling): विद्यालय स्तर पर शिक्षक सहायता प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएं जहां शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता दी जा सके।
- 3 . सामाजिक मान्यता: शिक्षक दिवस, नवाचार प्रतियोगिताएं और सम्मान समारोह जैसी पहलें उनके आत्मविश्वास को भराएंगी।
- 4 . प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास : सतत प्रशिक्षण (Continuous Professional Development) को आनिवार्य एवं प्रभावी बनाया जाए।
- 5 . कार्यस्थल का वातावरण: विद्यालयों में प्रशासनिक सहयोग, पर्याप्त शिक्षण संसाधन और प्रेरक वातावरण उपलब्ध कराया जाए।
- 6 . महिला शिक्षकों की विशेष सहायता: महिला शिक्षकों के लिए लचीला कार्य-समय और कार्यस्थल पर सुरक्षा-व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए।
- 7 . शिक्षक- छात्र अनुपात में सुधार : शिक्षकों पर बोझ घटाने के लिए रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाए।

भविष्य की दिशा (Scope for Further Research)

भविष्य में यह अध्ययन निम्न दिशाओं में विस्तारित किया जा सकता है

- 1 . बिहार के अन्य जिलों की तुलना करते हुए एक राज्यव्यापी तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
- 2 . शिक्षकों के डिजिटल अनुकूलन (Digital Adaptation) और Online Teaching Stress पर एक विशेष शोध की आवश्यकता है।
- 3 . शिक्षक के कार्य संतोष और छात्र परिणामों (Students Outcomes) के बीच संबंध का सांख्यिकीय अध्ययन किया जा सकता है।
- 4 . नीति निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ सूची (References)

- 1 . राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020), मानव संसाधन विकास मंत्रालय , भारत सरकार।
- 2 . NCF (2005), National Curriculum Framework, NCERT, New Delhi.
- 3 . RTE Act, 2009, Right to Education Act, Government of India.
- 4 . श्रीवास्तव, आर. (2016), "ग्रामीण बिहार में शिक्षकों की सामाजिक स्थिति का अध्ययन " भारतीय शिक्षा समीक्षा, 22(3), 115-127.
- 5 . कौशिक, एस.एवं सिंह, जे. (2018). "शिक्षकों का कार्य- संतोष और आर्थिक दशा" शैक्षणिक दृष्टि, 10(2), 45-53.
- 6 . N.C.E.R.T.(2021), Annual Status of Teachers Report.
- 7 . नीति आयोग (2019), State Education Index Report, भारत सरकार।
- 8 . विश्व बैंक (2020), Education and Human Capital in Bihar.
- 9 .Bihar Government. (2023). Economic Survey of Bihar. Government Publication.
10. Department of Education, Bihar. (2023). U-DISE School Data Report. Government of Bihar.
- 11.National Education Policy. (2020). Ministry of Education, Government of India.

12. Research Article on Teachers in Bhagalpur. (2025). [शोध पत्र का शीर्षक और प्रकाशक]

13. Tilka Manjhi Bhagalpur University. (2024). Teacher Training and Development Reports.

14. Media Reports on Education in Bihar. Various sources (2023-2024).

उपसंहार

शिक्षक समाज के निर्माण में वह धुरी हैं, जिनके बिना कोई भी शिक्षा नीति या सुधार स्थापी नहीं हो सकता। इसलिए नीति- निर्माताओं को चाहिए कि वे शिक्षकों के जीवन की जमीनी सच्चाई को समझें और ऐसे उपाय करें जिससे उनके आत्मबल, गरिमा और सामाजिक स्थिति पुनः सुदृढ़ हो सके।